



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

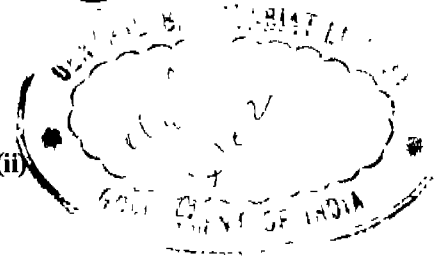
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 135]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 6, 2002/माघ 17, 1923

No. 135]

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 6, 2002/MAGHA 17, 1923

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 फरवरी, 2002

का.आ. 167(अ).— निम्नलिखित अधिसूचना, जिसे केन्द्रीय सरकार पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी करने की प्रस्थापना करती है, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, प्रकाशित की जाती है ; और सूचना दी जाती है कि उक्त अधिसूचना पर उस तारीख से जिसको इस अधिसूचना से युक्त भारत के राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा ;

उक्त प्रारूप अधिसूचना की बाबत कोई आक्षेप करने या सुझाव देने का इच्छुक कोई व्यक्ति उसे लिखित में केन्द्रीय सरकार के विचार के लिए इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर सचिव भारत सरकार, पर्यावरण और वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, सी०जी०ओ० काम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली 110003 को भेज सकेगा ।

प्रारूप प्रस्ताव

1. (क) माथेरन और उसके आसपास के प्रदेश को पारिस्थितिक संवेदनशील अंचल अधिसूचित करने का प्रस्ताव है । पारिस्थितिक संवेदनशील अंचल में माथेरन पर्वतीय स्थल नगर पालिका और उसके आसपास का क्षेत्र होगा । पारिस्थितिक संवेदनशील अंचल का मानचित्र उपाबंध-क में है । ग्रामों की सूची के साथ-साथ सीमा का वर्णन उपाबंध-ख में है ।

(ख) वन में सभी क्रियाकलाप (नगरपालिका क्षेत्र के भीतर और बाहर दोनों) भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69) के उपबंधों द्वारा शासित होंगे । अभयारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों में सभी क्रियाकलाप वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) के उपबंधों के द्वारा शासित होंगे ।

2. पारिस्थितिक संवेदनशील अंचल में विनियमित किए जाने वाले निम्नलिखित क्रियाकलापों की प्रस्थापना की जाती है :-

(क) पारिस्थितिक संवेदनशील अंचल के लिए मास्टर प्लान :-

- (i) पारिस्थितिक संवेदनशील अंचल के लिए मास्टर प्लान इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर महाराष्ट्र प्रादेशिक और नगर योजना अधिनियम 1966 के अधीन महाराष्ट्र सरकार द्वारा तैयार की जाएगी और भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा अनुमोदित की जाएगी। मास्टर प्लान में वन-विरहित क्षेत्रों के प्रत्यावर्तन, जलागम क्षेत्रों के प्रबंध, के लिए उपबंध, ईंधन लकड़ी, स्थानीय समुदाय की आवश्यकताओं के लिए उपबंध होगा और ऐसे क्षेत्र उपदर्शित होंगे जहां उद्योगों को अनुज्ञात किया जा सकेगा।
- (ii) पारिस्थितिक संवेदनशील अंचल के लिए मास्टर प्लान सभी विद्यमान गोथान, गोथान विस्तार क्षेत्रों, वनों, हरित क्षेत्रों, उद्यान कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों फलोद्यानों, जनजातीय क्षेत्रों जिसके अंतर्गत जनजातीय ग्रामरू भी है, प्राकृतिक झरनों, प्राकृतिक विरासत स्थलों और अन्य पर्यावरणिकी और पारिस्थितिकी क्षेत्रों को सीमांकित करेगी। हरित उपयोगों जैसे उद्यान कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, उद्यानों और अन्य ऐसे ही स्थानों से भूमि के उपयोग का कोई परिवर्तन पारिस्थितिक संवेदनशील अंचल के लिए मास्टर प्लान में केन्द्रीय सरकार पर्यावरण और वन मंत्रालय के पूर्व अनुमोदन के बिना गैर हरित उपयोगों और जनजातीय उपयोगों का गैर जनजातीय उपयोगों के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा। मास्टर प्लान में यातायात को, विशेषकर पारिस्थितिक संवेदनशील अंचल में जाने वाले यातायात को विनियमित करने के लिए उपाय भी इंगित किए जाएंगे और अनुबंधित अधिकथित किए जाएंगे।
- (iii) माथेरन नगर पालिका क्षेत्र के भीतर और बाहर क्षेत्रों में पृथक् क्षेत्र प्लान होंगे जो मास्टर प्लान के घटक के रूप में राज्य सरकार द्वारा तैयार की जा सकेगी और उस पर पर्यावरण और वन मंत्रालय की सहमति प्राप्त की जा सकेगी। 5,000 से अधिक जनसंख्या वाले पारिस्थितिक संवेदनशील अंचल में सभी निवासियों के लिए भी क्षेत्र विकास प्लान होने चाहिए। इनमें गोथान क्षेत्रों के लिए भवन निर्माण विनियमों को भी सम्मिलित किया जाएगा।
- (iv) पारिस्थितिक संवेदनशील अंचल के लिए मास्टर प्लान के तैयार होने और पर्यावरण और वन मंत्रालय के अनुमोदन तक अनुज्ञेय तल क्षेत्र अनुपात, अनुज्ञेय ऊंचाई, मंजिलों की अनुज्ञेय अधिकतम संख्या और माथेरन नगर पालिका सीमाओं में अनुज्ञेय भू सीमा क्षेत्र के विद्यमान प्राचलों में कोई वृद्धि नहीं होगी। स्टिल्ट्स, मेजेनाइन और बेसमेंट माथेरन नगर पालिका सीमाओं में अनुज्ञात नहीं की जाएगी। माथेरन नगर पालिका परिषद् पालिका क्षेत्र में नए सन्निर्माण पर पूर्ण रोक होगी। माथेरन नगर पालिका क्षेत्र से भिन्न क्षेत्रों में -

(फ) जनजातीय क्षेत्र /वन अंचल /हरित अंचल/कृषि अंचल में कोई कमी नहीं होगी।

- (ख) भवनों की आन्त्यतिक ऊँचाई 9 मीटर से अधिक नहीं होगी और मंजिलों की संख्या भूतल धन एक से अधिक नहीं होगी ।
- (ग) उपाबंध-ग में उल्लिखित क्रियाकलाप राज्य/स्थानीय नियमों और विनियमों के अधीन रहते हुए निगरानी समिति द्वारा अनुज्ञात किए जा सकेंगे ।
- (घ) पारिस्थितिक संवेदनशील अंचल के अन्य क्षेत्रों में किसी नए सन्निर्माण के लिए निगरानी समिति का पूर्व अनुमोदन अपेक्षित होगा ।

(ख) औद्योगिक ईकाईयां :-

- (i) उद्योगों की अवस्थिति केवल अभिहित औद्योगिक क्षेत्रों या संपदाओं में होगी और वह महाराष्ट्र सरकार द्वारा तय किए गए मार्गदर्शनों और पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी किए गए मार्गदर्शनों के अनुसार होगी ।
- (ii) मार्गदर्शन तय करते समय, मास्टर प्लान ऐसे उद्योगों को जो पूर्णतया: प्रतिषिद्ध किए गए हैं, विनिर्दिष्ट करेगी, उनको जो आंकलन के पश्चात् अनुज्ञात किए जा सकते हैं जिनकी अपेक्षाएं और प्रक्रियाएं विनिर्दिष्ट की जाती हैं और उनको जो अनुज्ञात किए जा सकेंगे बशर्ते कि कतिपय मानदंड पूरे कर दिए जाते हैं जो विनिर्दिष्ट किए जाने चाहिए ।
- परंतु इन मार्गदर्शनों की किसी बात से समय-समय पर यथासंशोधित केन्द्रीय सरकार की 27 जनवरी, 1994 की पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना के उपबंधों का विरोध नहीं होगा ।
- (iii) भविष्य में केवल अप्रदूषित, अपरिसंकटमय लघु उद्योग और सेवा उद्योगों, पुष्प कृषि, उद्यान कृषि या कृषि आधारित ऐसे उद्योगों जो पारिस्थितिक संवेदनशील अंचल से देशी माल से उत्पादों का उत्पादन करती हैं इस अंचल में अनुज्ञात किया जाएगा ।

(ग) खदान क्रिया और खनन :- खदान क्रिया और खनन क्रियाकलाप पारिस्थितिक संवेदनशील अंचल में प्रतिबंधित होंगे । पारिस्थितिक संवेदनशील अंचल में कोई नया खनन पट्टा अनुदत्त नहीं किया जाएगा तथापि, निगरानी समिति माथेरन नगर पालिका परिषद् क्षेत्र में स्थानीय निवासीय गृह निर्माण के सन्निर्माण और परंपरागत सड़क बनाने और अनुरक्षण संक्रमण के लिए अपेक्षित सामग्रियों की सीमित खदान क्रिया के लिए विशेष अनुज्ञा देने के लिए प्राधिकारी होगी ;

परंतु ऐसी खदान क्रिया सीधी पहाड़ी ढलान या अधिक कटाव वाले क्षेत्रों पर या वा. भूमि पर नहीं की जाती हो ।

(घ) वृक्ष :- पारिस्थितिक संवेदनशील अंचल के भीतर की भूमि चाहे वन, सरकारी, राजस्व या निजी भूमि हो, वन भूमि की दशा में राज्य सरकार और सरकारी, राजस्व और निजी भूमि की दशा में संबंधित जिला कलेक्टर की बिना पूर्व अनुज्ञा के जो उस प्रक्रिया के अनुसार होगी जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाएगी कोई वृक्ष नहीं गिराया जाएगा, परंतु यह कि जिला कलेक्टर इस शक्ति को उपखंड अधिकारी की पंक्ति से नीचे के किसी अधीनस्थ अधिकारी को प्रत्यायोजित नहीं करेगा ।

(ड) पर्यटन :- पर्यटन क्रियाकलाप भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय के परामर्श से और पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा अनुमोदित राज्य सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा तैयार की जाने वाली विशेषकर पारिस्थितिक पर्यटन, पारिस्थितिक शिक्षा और पारिस्थितिक विकास पर्यटन मास्टर प्लान के अनुसार होंगे। पर्यटन मास्टर प्लान आंचलिक मास्टर प्लान का एक घटक रूप भी होगी। जब तक पर्यटन मास्टर प्लान पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा अनुमोदित नहीं कर दी जाती है तब तक माथेरन नगर पालिका परिषद् के भीतर नई और अतिरिक्त पर्यटन सुविधाएं जैसे होटल, रेस्टोरेंट्स, सराय, लॉजिंग और बोर्डिंग हाऊस आदि पर प्रतिबंध होगा।

पर्यटन मास्टर प्लान पारिस्थितिक संवेदनशील अंचल के चलाये जाने की क्षमता के विस्तृत अध्ययन पर आधारित होगी जो राज्य सरकार द्वारा की जाएगी और इस अधिसूचना की तारीख से 2 वर्ष के भीतर अनुमोदन के लिए पर्यावरण और वन मंत्रालय को भेजी जाएगी। सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप पर्यटन के लिए विकास/ पर्यटन क्रियाकलाप जो विद्यमान है, के विस्तार की अनुज्ञा केवल इस पर्यटन प्लान या चलाए जाने की क्षमता के अध्ययन की परिसीमाओं के भीतर ही दी जाएगी। अनुमोदन के लिए पर्यावरण और वन मंत्रालय को भेजे जाने तक नए पर्यटन क्रियाकलाप और पर्यटन के लिए विकासों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा अधिकथित मार्गदर्शनों के अध्याधीन निगरानी समिति द्वारा विस्तृत विश्लेषण किए जाने और अनुमोदित किए जाने के पश्चात् ही अनुज्ञापित किया जाएगा।

(च) प्राकृतिक विरासत :- अंचल में मूल्यवान प्राकृतिक विरासत के स्थलों की पहचान विशिष्ट रूप से, चट्टान निर्माणों, जल प्रपातों, फूलों, झरनों, तंगघाटियों, उपवनों, गुफाओं, स्थलों, सैरों, सवारियों इत्यादि के रूप में की जाएगी और प्लानों को उनके प्राकृतिक स्थापन में उनके संरक्षण को मास्टर प्लान में सम्मिलित किया जाएगा। इन स्थलों पर या उनके निकट सन्निर्माण क्रियाकलापों को रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा कठोर मार्गदर्शन तय किए जाएंगे जिसके अंतर्गत पर्यटकों को सुविधा उपलब्ध कराने के लिए व्यवस्था भी है। अंचल में सभी जीन पूल आरक्षित क्षेत्रों को परिरक्षित किया जाएगा। राज्य सरकार इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष के भीतर उनके संरक्षण या परिरक्षण के लिए उचित प्लान तैयार करेगी। ये प्लान मास्टर प्लान के भाग रूप होंगे।

(छ) मानव निर्मित विरासत :- ऐतिहासिक, स्थापत्य, सौंदर्यपरक और सांस्कृतिक महत्व के भवनों, संरचनाओं, आर्टिफेक्टों, क्षेत्रों और प्रसीमाओं की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण, विशेषकर उनके बाहरी स्वरूप (और जहां उचित समझा जाए, वहां अंदरूनी स्वरूप) के संरक्षण की याजना तैयार की जाएगी और उसे इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष के भीतर मास्टर प्लान में सम्मिलित किया जाएगा। राज्य सरकार, पारिस्थितिक संवेदनशील अंचल में, विशेष रूप से माथेरन नगर पालिका सीमाओं में भवन और अन्य क्रियाकलापों का विनियमन करने के लिए मार्गदर्शन सिद्धांत बना सकेगी, जिससे कि शहरों का और पारिस्थितिक संवेदनशील अंचल का विशेष स्वरूप और सुभिन्न परिवेश बनाए रखा जा सके।

(ज) विरासत स्थलों (प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों) पर या उनके आसपास विकास या सन्निर्माण क्रियाकलापों का विनियमन, पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा 1995 में बनाए गए, समय-समय पर यथा संशोधित और सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को परिचालित प्राकृतिक और मानव निर्मित स्थलों के लिए माडल, विनियमों या राज्य सरकार के किन्हीं अन्य कानूनी उपबंधों, जो भी कठोरतर हो, के अनुसार किया जाएगा।

(झ) भूगर्भ जल :- भूगर्भ जल के निष्कर्षण की अनुज्ञा केवल प्लाट के स्वामी के सदभावी कृषि और घरेलू उपभोग के लिए दी जाएगी। औद्योगिक/वाणिज्यिक/आवासीय संपदा/कम्प्लेक्सों के लिए भूगर्भ जल के निष्कर्षण के लिए राज्य भूगर्भ जल बोर्ड की पूर्व अनुज्ञा अपेक्षित होगी। भूगर्भ जल के विक्रय की निगरानी समिति के पूर्व अनुमोदन के बिना अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

(ञ) प्लास्टिक का उपयोग :- पारिस्थितिक संवेदनशील अंचल के भीतर प्लास्टिक और टेढ़ापेकों का उपयोग निगरानी समिति द्वारा विनियमित किया जाएगा। माथेरन नगर पालिका सीमाओं के भीतर प्लास्टिक की थैलियों पर पूर्ण प्रतिबंध होगा।

(ट) पहाड़ी ढलान का संरक्षण :- मास्टर प्लान पहाड़ी ढलान पर ऐसे क्षेत्रों को उपदर्शित करेगी जहां सन्निर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा और सीधी पहाड़ी ढलान पर या अधिक कटाव वाले क्षेत्र पर कोई सन्निर्माण नहीं होगा।

(ठ) बहिस्रावों का निष्सारण :- पारिस्थितिक संवेदनशील अंचल के भीतर किसी अनुपचारित बहिस्राव का निष्सारण प्रतिषिद्ध है। किसी बहिस्राव का चाहे वह उपचारित हो अथवा अनुपचारित अंचल के भीतर किसी जलाशय/जल स्रोत में निष्सारण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(ड) ठोस अपशिष्ट :- स्थानीय प्राधिकारी ठोस अपशिष्ट को जैव निम्नीकरणीय और जैव अनिम्नीकरणीय घटकों में पृथक् करने प्लान योजना बनाएंगे। जैव निम्नीकरणीय सामग्री अधिमानतः कंपोस्टिंग या कृमि पालन द्वारा पुनः चक्रित की जा सकेगी; अकार्बनिक सामग्री पर्यावरणीय रूप से स्वीकार्य अवस्थानों पर व्यव्यनित की जा सकेगी। ठोस अपशिष्टों का जलाना या भस्मीकरण माथेरन नगर पालिका क्षेत्र के भीतर अनुज्ञेय नहीं होगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि ठोस अपशिष्ट पद में, घरेलू, औद्योगिक, वाणिज्यिक और उद्यान संबंधी अपशिष्ट भी सम्मिलित हैं।

(ढ) प्राकृतिक झरने :- सभी प्राकृतिक झरनों के जल आगम क्षेत्र की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण के लिए प्लान और जो सूख गए हैं उनके प्राकृतिक संस्थापन में उनके पुनर्नवीकरण को मास्टर प्लान में सम्मिलित किया जाएगा। इन क्षेत्रों में या उनके निकट विकास क्रियाकलापों पर प्रतिबंध लगाने के लिए सरकार द्वारा कठोर मार्गदर्शन तैयार किए जाएंगे।

(ण) यातायात :- कोई यानीय यातायात सिवाय एंबुलेंस और फायर इंजन के, माथेरन नगर पालिका सीमाओं के भीतर अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

3. निगरानी समिति :

- (क) भारत सरकार का पर्यावरण और वन मंत्रालय इस अधिसूचना के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक निगरानी समिति गठित करेगा। अधिसूचना के उपरोक्त उपबंधों के अतिरिक्त निगरानी समिति को पारिस्थितिक संवेदनशील अंचल के भीतर

ध्वनि प्रदूषण को विनियमित और नियंत्रित करने की शक्ति होगी । पर्याप्त प्रबंधकीय/प्रशासनिक अनुभव वाला और स्थानीय समस्याओं को समझने वाला एक उत्कृष्ट/प्रख्यात व्यक्ति समिति की अध्यक्षता करेगा । निगरानी समिति में पर्यावरण और वन मंत्रालय, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि और पर्यावरण (जिसके अंतर्गत विरासत संरक्षण भी है) के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों के कम से कम दो प्रतिनिधि सम्मिलित होंगे । महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले का कलेक्टर सदस्य/संयोजक होगा । समिति की सदस्यता जिसके अंतर्गत अध्यक्ष भी है दस से अधिक नहीं होगी ।

(ख) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन शिकायत फाइल करना निगरानी समिति का कर्तव्य होगा यदि उक्त अधिनियम के अधीन अपराध उसकी जानकारी में आते हैं ।

(ग) समिति या समिति द्वारा प्राधिकृत निगरानी समिति का कोई अधिकारी या सदस्य पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अधीन शिकायत फाइल करने के लिए प्राधिकृत होगा ।

4. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 23 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों प्रयोग करते हुए, पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार ऐसे कृत्यों का विशेष रूप से जिनका अधिसूचना में उल्लेख किया गया है निर्वहन करने और उनकी आनुषंगिक सभी बातों को करने के लिए (सिवाय वे कृत्य जो समय समय पर यथा संशोधित 27 जनवरी, 1994 की पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना के उपबंधों के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा संपादित किए जाने अपेक्षित हैं) निगरानी समिति को सशक्त करता है ।

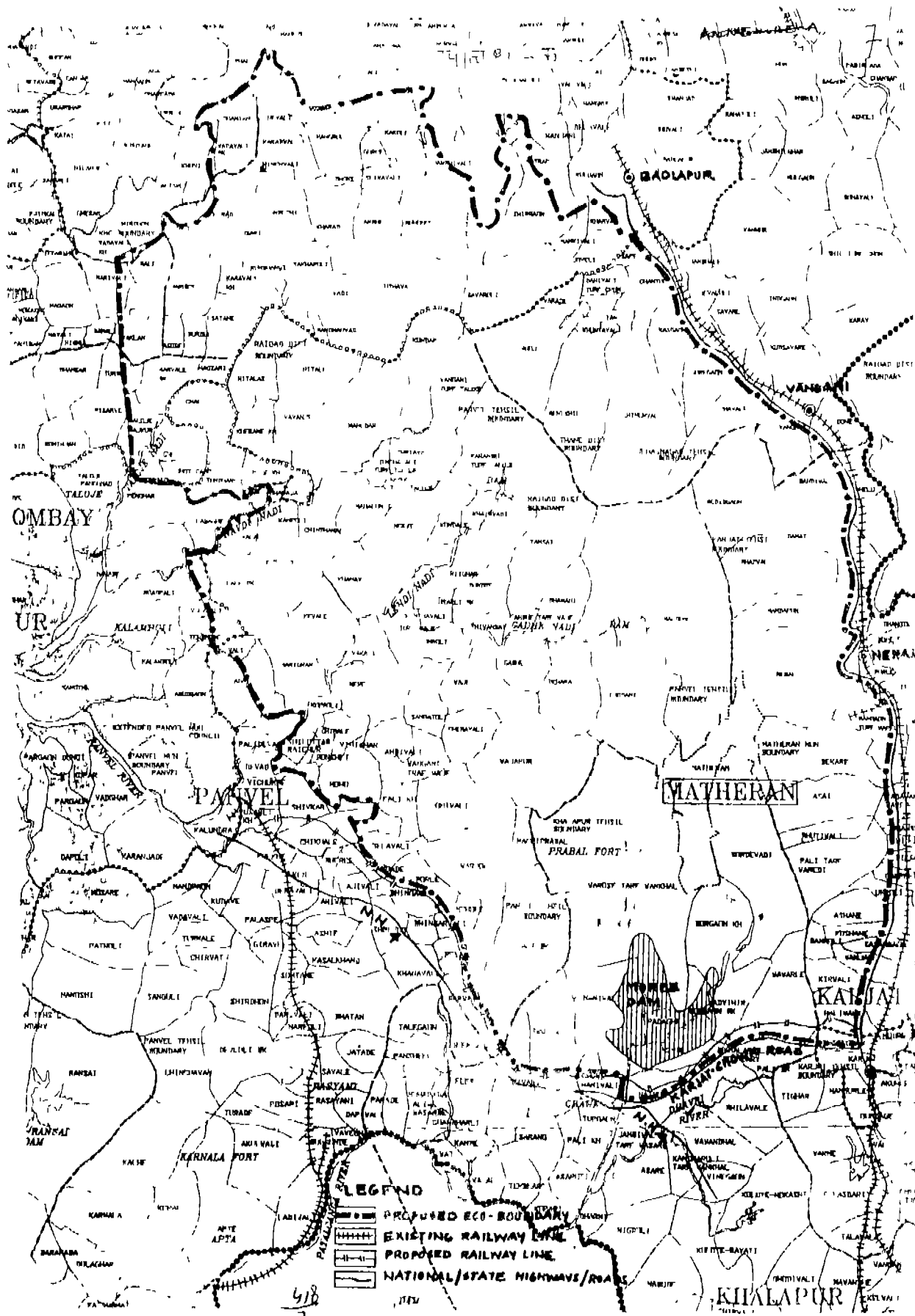
5 अपील :

(क) निगरानी समिति के किसी आदेश से अपील पर्यावरण और वन मंत्रालय में होगी : परंतु यह कि अपील प्रभावित व्यक्ति/व्यक्तियों, संस्थाओं/संगठनों द्वारा आदेश की प्राप्ति की तारीख से साठ दिन के भीतर की जाएगी ।

(ख) पर्यावरण और वन मंत्रालय अपील की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर अपील का निपटान करेगा ।

[फा. सं. जे-20011/1/99-आई. ए.-III]

डॉ. बी. राजगोपालन, संयुक्त सचिव



उपाबंध -ख

माथेरन पारिस्थितिक संवेदनशील अंचल

पूर्व: नेरल और वांगानी से होकर उत्तर पूर्व में बदलापुर की उर्बानीसेबल -1 अंचल को दक्षिण पूर्व में कर्जात से सड़क ।

उत्तर: उत्तर-पूर्व में बदलापुर से उत्तर-पश्चिम में नवी मुम्बई नगर निगम की उत्तरी सीमाओं तक वन अंचल/हरित-1 अंचल/हरित-2 अंचल/औद्योगिक अंचल सहित खदान अंचल/उर्बानीसेबल-1 अंचल/उर्बानीसेबल--2 अंचल की सीमा ।

पश्चिम: उत्तर-पश्चिम में नवी मुम्बई नगर निगम की उत्तरी सीमाओं से दक्षिण-पश्चिम में चौक तक वन अंचल/हरित-1 अंचल/हरित-2 अंचल/खदान अंचल तक वन अंचल/हरित-1 अंचल/हरित-2 अंचल/औद्योगिक अंचल सहित खदान अंचल/उर्बानीसेबल-1 अंचल/उर्बानीसेबल--2 अंचल की सीमा जहां पश्चिम-दक्षिण-पश्चिम में पनवेल-कर्जात रेल लाइन से मिलती है, तब मोर्बे डेम के आउटफ्लो तक रेल लाइन के साथ और तब चौक कर्जात सड़क से मिलने तक आउटफ्लो के साथ ।

दक्षिण: जहां मोर्बे डेम का आउटफ्लो दक्षिण-पश्चिम में चौक कर्जात सड़क पार करता है से दक्षिण-पूर्व में कर्जात तक ।

उपरोक्त आबद्ध अंचल से :-

(क) कर्जात नगर पालिका का क्षेत्र अपवर्जित किया जाता है

(ख) नेरल और वांगानी में तैयार की गई ले आउट के अधीन क्षेत्र जो अंतिम प्रादेशिक प्लान 1973 का भाग रूप है अपवर्जित की जाती है ।

मेथारन का संपूर्ण नगर पालिका क्षेत्र सम्मिलित किया गया है ।

टिप्पण: उपरोक्त निर्दिष्ट अंचलों का वर्गीकरण मुम्बई महानगर प्रदेश, दिसंबर 1999 की मंजूरशुदा प्रादेशिक प्लान के अनुसार है ।

माथेरन पारिस्थितिक संवेदनशील अंचल के ग्रामों की सूचीजिला: रायगढ़तहसील:कर्जात

क्र.सं.	ग्राम	
1	असई	
2	अशाणे	भागतः
3.	बामनौली	
4	बंदीबली	
5	बदिस गांव	
6	बेकारे	
7	भडवाल	
8	भांसोली	भागतः
9	भूतीवाली	भागतः
10	बोरले	भागतः
11	चिंचवाली	भागतः
12	दमात	भागतः
13	दमोते	भागतः
14	दिकसल	भागतः
15	गर्पोली	भागतः
16	हलीवली	भागतः
17	जिते	भागतः
18	किरवाली	भागतः
19	कोशाणे	भागतः
20	माम्दापुर	भागतः
21	मानगांव टर्फ वरेडी	भागतः
22	माथेरन	भागतः

23	नेरल	भागतः
24	पाली टर्फ वरेड़ी	
25	सावरगांव	भागतः
26	शेलू	भागतः
27	उपरोली	भागतः
28	वड़ावाली टर्फ वरेड़ी	भागतः
29	वंजाले	भागतः

टिप्पण: माथेरन का संपूर्ण नगर पालिका क्षेत्र सम्मिलित किया गया है।

तहसील: खालापुर

क्र.सं.	ग्राम		
1.	भिलावाले	भागतः	ग्राम
2.	बोरगांव बीके.		
3	बोरगांव केएच.		
4	चौक मनीवाली	भागतः	
5	हतनौली	भागतः	
6	लोधीवली	भागतः	
7	मोर्बे		
8	नाधल	भागतः	
9	नानीवाली		
10	पडाघे		
11	पाली बीके.	भागतः	
12	सोंदेवाड़ी		
13	वाड विहार		
14	वारोस टर्फ वंखल		

15	वावर्ले	भागतः
----	---------	-------

तहसील: पन्वेल

क्र.सं.	ग्राम	
1	अदई	
2	अकुर्ली	
3	अंभे टर्फ तलोजे	
4	अंभे टर्फ वाजे	
5	अंबेवाली	
6	बारवाई	भागतः
7	बेरावाली	
8	भिगर	भागतः
9	भोकरपाड़ा	भागतः
10	बोंसेट	
11	बोर्ले	भागतः
12	चाल	
13	चेरावाली	
14	चिखाले	भागतः
15	चिंचावाली टर्फ तलोजे	
16	चिंचावाली टर्फ वाजे	
17	चिंधारन	
18	चिपाले	
19	देहारंग	
20	देवाड	भागतः
21	देवीचपाड़ा	भागतः
22	धमानी	
23	धोदानी	

24	दुंद्रे	
25	गाधे	
26	घोट	
27	घोट कैप	
28	हरिग्राम	
29	हेडूटाणे	
30	कानपोली	
31	करम्बेली टर्फ तलोजे	
32	करावेले बीके.	
33	केवाले	
34	खैरवाड़ी	
35	खानव	
36	खैराणे केएच.	
37	कोंडाले	
38	कोंडप	
39	कोपरोली	
40	लोनीवाली	
41	माचीप्राबल	
42	महालुंगी	
43	महोदर	
44	मालडुंगे	
45	मोहो	भागतः
46	मोहोपे	भागतः
47	मोर्बे	
48	नागजरी	
49	नेरे	
50	नेवाली	

51	नितालस	
52	निताले	
53	पाले बीके.	
54	पाली बीके.	
55	पाली केएच.	
56	पेंघार	भागतः
57	पोयजे	भागतः
58	रिजघार	
59	रोडपाली	भागतः
60	संगाडे	भागतः
61	संगाटोली	
62	शिलोत्तर रायचूर	
63	सिरवाली	
64	शिवांसाए	
65	शिवकार	भागतः
66.	तलोजे मजकुर	भागतः
67.	तमसाई	
68.	तेमबोडे	भागतः
69.	तोंघारे	भागतः
70.	तुर्भे	भागतः
71.	उमरोली	
72.	उसरली बीके.	
73.	वाकाड़ी	
74.	वलाप	
75.	वालावली	भागतः
76.	वावंजे	
77.	विहिघर	

78.	वाजपुर	
79.	वाजे	
80.	वांगानी टर्फ तलोजे	
81.	वांगानी टर्फ वाजे	
82.	वारडोली	

जिला: थाणे

तहसील: कल्याण

क्र.सं.	ग्राम	
1	भाल	भागतः
2	धामतान	भागतः
3	द्वारली	भागतः
4	वाडावाली बीके.	
5	वासार	भागतः

तहसील: थाणे

क्र.सं.	गांव	
1	बाले	
2	नारिवाली	भागतः
3	वकलान	भागतः

तहसील: उल्हासनगर

क्र.सं.	गांव	
1	अंभे	
2	अंबोशी	
3	असोडे	
4	बंधनवाड़ी	

5	बंदशील	
6	भोज	
7	बोहोनोली	
8	बुर्दल	
9	चमतोली	
10	चिखलोली	
11	चिचवाली	
12	चिचवाली बीके.	
13	चिराड	
14	दहीवाली टर्फ चोन	
15	दहावाले	
16	धोक	
17	डोन	
18	गोरेगांव	
19	गोर्प	
20	जंभीवाली	
21	जोवेली	
22	काकड़वाल	
23	कोकोले	
24	कारावाले केएच.	
25	कासगांव	भागतः
26	कटरप	भागतः
27	खर्ड	
28	खारवाई	भागतः
29	खुंटावाली	
30	कुभर्ली	
31	कुशावाली	

32	मंगरूल	
33	मंजरले	भागतः
34	मंकीवाली	भागतः
35	नारहन	
36	नेवेली	
37	पेले	भागतः
38	पाली	भागतः
39	पोसारी	
40	सखरोली	
41	सेप	भागतः
42	सेवेरोली	
43	शिरावाली	
44	शिरगांव	भागतः
45	तान	
46	ऊसातेने	
47	वंगानी	भागतः
48	वराडे	
49	वाड़ी	

उपाबंध –ग

माथेरन पारिस्थितिक संवेदनशील अंचल में अनुज्ञेय विकासोन्मुख क्रियाकलाप

(अंचलों का वर्गीकरण मुम्बई महानगर प्रदेश, दिसंबर 1999 की मंजूरशुदा प्रादेशिक प्लान के अनुसार है)

1. वन अंचल

- 1.1 जब कोई भूमि उच्चतम न्यायालय के तारीख 12.12.1996 के आदेश के अनुसार यथा परिभाषित आरक्षित वन, संरक्षित वन, अधिगृहीत वन के बाहर स्थित है ; ऐसी भूमि का विकास हरित अंचल-2 के उपबंधों के अनुसार विनियमित होगी ।

2. हरित अंचल-2

2.1 हरित अंचल-2 (जी-2 अंचल) में अनुज्ञेय उपयोग निम्नानुसार हैं :

- (क) भूमि की बेहतर जोत के लिए उपयोग करने के लिए कृषि के प्रयोजन के लिए निर्धारित या धारित किसी भूमि के धारक के वास्तविक उपयोग के लिए फार्म भवन । परंतु यह कि कृषि भूमि का क्षेत्र 0.4 हे. या अधिक हो ।
- (ख) उद्यान कृषि, पुष्प कृषि और कृषि और चावल की सहबद्ध क्रियाकलाप तथा पोहा मिल, कुक्कुट फार्म, पशुशाला, सूकरालय और भेड़ फार्म
- (ग) धार्मिक स्थान, शमशान और कब्रिस्तान ।
- (घ) 0.4 हे. से अन्यून के प्लॉट पर विद्यालय, पूर्व प्राथमिक विद्यालय और स्वास्थ्य केन्द्र ।
- (ङ) क्लिनिक और औषधालय ।
- (च) सड़क और पुल, रेल, बांध, पाईपलाइन, विद्युत पारेषण लाईन, संचार टावर

2.2 न्यूनतम प्लॉट का आकार 0.4 हे. होगा ।

2.3 एफएसआई और भू सीमा क्षेत्र

2.1 में अनुज्ञेय उपयोग	एफएसआई	भू सीमा क्षेत्र
क)	सभी भवनों की कुर्सी का आकार 150 वर्ग मीटर से अधिक नहीं होगा	
ख) ग) घ) ङ)	0.05	5 %

3. हरित अंचल-1

3.1 हरित अंचल -1 में अनुज्ञेय क्रियाकलाप निम्न प्रकार हैं :

- (क) भूमि के बेहतर जोत के लिए उपयोग के लिए कृषि के प्रयोजन के लिए निर्धारित या धारित किसी भूमि के धारक के वास्तविक उपयोग के लिए फार्म भवन । परंतु यह कि कृषि भूमि का क्षेत्र 0.4 हे. या अधिक हो ।
- (ख) हॉलीडे रिसोर्ट्स और हॉलीडे होम ।
- (ग) 2.5 हे. से अन्यून के प्लॉट पर कर्मचारिवृंद के लिए आवासीय क्वार्टरों के साथ-साथ शैक्षिक, चिकित्सीय, सामाजिक , सांस्कृतिक और धार्मिक संस्थाएं ।

- (घ) 0.4 हे. से अन्यून के प्लाट पर विद्यालय, पूर्व प्राथमिक विद्यालय और स्वास्थ्य केन्द्र ।
- (ङ) क्लिनिक, औषधालय और स्वास्थ्य केन्द्र ।
- (च) एलपीजी सिलेंडरों का भंडारण ।
- (छ) उद्यान कृषि, पुष्प कृषि और कृषि और चावल की सहबद्ध क्रियाकलाप तथा पोहा मिल, कुक्कुट फार्म, पशुशाला, सूकरालय और भेड़ फार्म ।
- (ज) धार्मिक स्थान, शमशान और कब्रिस्तान ।
- (झ) उद्यान, बाग, खेल मैदान, तरणताल, शिविर मैदान ।
- (ञ) सड़क और पुल, रेल, बांध, पाईपलाईन, विद्युत पारेषण लाईन, संचार टावर ।
- 2 न्यूनतम प्लाट आकार 0.4 हे. होगा ।
- 3 एफएसआई और भू सीमा क्षेत्र

3.1 में अनुज्ञेय उपयोग	एफएसआई	भू सीमा क्षेत्र	
क)	सभी भवनों की कुर्सी का आकार 150 वर्ग मीटर से अधिक नहीं होगा		
ख) से ङ)	0.1	10 %	
अन्य	0.05	5 %	

4. उर्बानीसेबल अंचल-2

4.1 उर्बानीसेबल अंचल-2 में अनुज्ञेय क्रियाकलाप निम्न प्रकार है :

- (क) भूमि के बेहतर जोत के लिए उपयोग के लिए कृषि के प्रयोजन के लिए निर्धारित या धारित किसी भूमि के धारक के वास्तविक उपयोग के लिए फार्म भवन । परंतु यह कि कृषि भूमि का क्षेत्र 0.4 हे. या अधिक हो ।
- (ख) आवासीय प्रयोजनों के लिए आवास ।
- (ग) फुटकर दुकानें, थोक दुकानें , रेस्टोरेंट और बैंक
- (घ) सरकारी कार्यालय
- (ङ) 0.4 हे. से अन्यून के प्लाट पर विद्यालय, पूर्व प्राथमिक विद्यालय और स्वास्थ्य केन्द्र ।
- (च) क्लिनिक, औषधालय और स्वास्थ्य केन्द्र ।
- (छ) अप्रदूषणकारी वैज्ञानिक संस्थाएं
- (ज) गेरेज, पेट्रोल पंप, आटोमोबाईल मरम्मत कार्यशाला ।

- (झ) उद्यान, बाग, खेल मैदान, तरणताल ।
- (ञ) कब्रिस्तान और शमशान ।
- (ट) उद्यान कृषि, पुष्प कृषि और कृषि और चावल की सहबद्ध क्रियाकलाप तथा पोहा मिल, कुक्कुट फार्म, पशुशाला, सूकरालय और भेड़ फार्म ।
- (ठ) निगरानी समिति के पूर्व अनुमोदन से होटल पर्यटन रिसोर्ट, होलीडे होम, मोटल ओर क्लब हाऊस ।
- (ड) निगरानी समिति के पूर्व अनुमोदन से लोक सेवाएँ और जल उपचार संयंत्र की उपयोगिता स्थापन, मल उपचार संयंत्र, ठोस अपशिष्ट उपचार और व्ययन सुविधाएँ, विद्युत सब-स्टेशन, गैस संकर्म, फायर ब्रिगेड, पुलिस थाना, टेलीफोन एक्सचेंज, बस शेल्टर, टर्मिनल्स और डिपो
- (ढ) सड़क, पुल, बांध, रेल लाईन और संबंधित सुविधाएँ, पाईप लाईन विद्युत पारेषण लाईन और संचार टावर

4.2 न्यूनतम प्लॉट आकार 2,000 वर्ग मीटर होगा

4.3 अनुज्ञेय एफएसआई 0.2 से अधिक नहीं होगी

4.4 अनुज्ञेय भू सीमा क्षेत्र 20 % से अधिक नहीं होगा

5. उर्बानीसेबल अंचल-1

5.1 माथेरन के लिए मास्टर प्लान तैयार करने में माथेरन शीर्षक रिपोर्ट की सिफारिशें : मुम्बई महानगर प्रदेश-विरासत संरक्षण सोसायटी द्वारा आरंभ किए गए व्यापक विरासत सूचीबद्ध प्रस्ताव विचार में लिए जाएंगे ।

5.2 नेरल और वांगानी की उर्बानीसेबल अंचल-1 के भीतर भूमि का विकास जिसके लिए कोई विकास प्लान, प्लान प्रस्ताव, शहरी प्लान स्कीम या विकास नियंत्रण विनियम विद्यमान नहीं है हरित अंचल-2 के लिए उपबंधों के अनुसार विनियमित होगी ।

6 गोथान और गोथान विस्तार

6.1 अंचलों का विचार न करते हुए निम्नलिखित उपबंधों से गोथान और गोथान विस्तार विनियमित होंगे ।

6.2 गोथान की सीमा वह होगी जो राजस्व मानचित्र में दर्शित की गई थी जब प्राचीन प्लान प्रवृत्त हुई ।

6.3 गोथान विस्तार गोथान सीमा से 200 मीटर से भीतर का क्षेत्र है । यदि किसी प्लॉट का प्लॉट का तीन चौथाई से अधिक 200 मीटर के भीतर आता है तब संपूर्ण प्लॉट गोथान विस्तार का भाग रूप समझा जाएगा । गोथान विस्तार के भीतर की भूमि का केवल गोथान के वास्तविक निवासियों के लिए/द्वारा उपयोग होगा ।

6.4 गोथान में भूमि निम्नलिखित प्रयोजनों में किसी के लिए प्रयुक्त की जा सकेगी ।

- (क) आवासीय
- (ख) फुटकर दुकान, रेस्टोरेंट, बैंक, नाई की दुकान, आटा चक्की, राशन दुकान, साईकिल मरम्मत की दुकान, आटोमोबाईल मरम्मत की दुकान
- (ग) विद्यालय
- (घ) सामुदायिक केन्द्र और अन्य सामाजिक संस्थाएं
- (ङ) धार्मिक स्थान
- (च) क्लिनिक औषधालय और स्वास्थ्य केन्द्र
- (छ) आवश्यक लोकसेवाएं और उपयोगिताएं जिसके अंतर्गत स्थानीय सरकारी कार्यालय भी हैं
- (ज) प्रत्येक प्लॉट पर 5 पशुओं की सीमा के अधधीन पालतु पशुओं के लिए पशुशाला
- (झ) परम्परागत घरेलू उद्योग
- (ञ) फसल, चारा, खाद, कृषि उपस्कर और अन्य वैसी ही आवश्यकताओं का भंडारण
- (ट) उद्यान, बाग और खेल मैदान
- (ठ) जन सुविधाएं
- (ड) घरेलू और वाणिज्यिक प्रयोजनों जैसे होटल, रेस्टोरेंट और यात्री निवासों के लिए ईंधन का भंडारण ।

6.5 एफएसआई और भू सीमा क्षेत्र :

क्षेत्र	एफएसआई	भू सीमा क्षेत्र
गोथान	1.00	-
गोथान विस्तार	0.40	40 %

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 6th February, 2002

S.O. 167(E).— The following notification which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (v) of sub-section 2 of Section 3 of the Environment (Protection) Act 1986 (29 of 1986) is hereby published as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 for information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette of India containing this notification are made available to the public;

Any person desirous of making any objection or suggestion in respect of the said draft notification may forward the same in writing for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary to the Government of India, Ministry of Environment & Forests, Paryavaran Bhavan, CGO Complex, Lodi Road, New Delhi 110 003.

DRAFT PROPOSALS

1. (a) It is proposed to notify Matheran and surrounding region as an Eco Sensitive Zone. The Eco Sensitive Zone shall consist of Matheran Hill Station Municipality and its environs. The map of the Eco Sensitive Zone is at Annexure-A. The description of the boundary along with the list of villages is at Annexure-B.
- (b) All activities in the forest (both within and outside municipal areas) shall be governed by the provisions of the Indian Forests Act, 1927 (16 of 1927) and Forest (Conservation) Act 1980 (69 of 1980). All activities in the sanctuaries and national parks shall be governed by the provisions of the Wildlife (Protection) Act, 1972 (53 of 1972).
2. The following activities are proposed to be regulated in the Eco Sensitive Zone, namely: -
 - (a) **Master Plan for Eco-sensitive zone: --**
 - (i) Master plan for the Eco-Sensitive Zone shall be prepared by the State Government under the Maharashtra Regional and Town Planning Act 1966 within a period of two years from the date of publication of this notification and approved by the Ministry of Environment and Forests in the Government of India. The Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, management of catchment areas, provision for fuel wood, needs of local community and indicate areas where industries may be permitted.
 - (ii) The Master Plan for Eco-sensitive zone shall demarcate all the existing gaothans, gaothan expansion areas, forests, green areas, horticultural areas, agricultural areas, orchards, tribal areas including tribal hamlets, natural springs, natural heritage sites and other environmentally and ecologically sensitive areas. No change of land use

from green uses such as horticulture areas, agriculture, parks and other like places to non-green uses and tribal uses to non-tribal uses shall be permitted in the Master Plan for Eco-sensitive zone without the prior approval of the Central Government in the Ministry of Environment and Forests. The Master Plan shall also indicate measures and lay down stipulations for regulating traffic, especially through traffic in the Eco Sensitive Zone.

- (iii) The areas within and outside Matheran municipal area shall have separate area Plans which may be prepared by the State Government as a component of the Master Plan and concurrence of the Ministry of Environment & Forests shall be obtained on this. All habitations in the Eco-Sensitive Zone having populations of more than 5000 should also have Area Development Plans. These shall include building regulations for the gaathan areas
- (iv) Pending the preparation of and approval by the Ministry of Environment & Forests to the Master Plan for Eco-sensitive zone there shall be no increase in the existing parameters of permissible Floor Area Ratio, permissible height, permissible maximum number of storeys and permissible coverage in Matheran Municipal limits. Stilts, Mezzanines and basements shall not be permitted in Matheran Municipal limits. There shall be a total ban on new construction in the Matheran Municipal council area. In areas other than Matheran Municipal area
 - a) There shall be no reduction in the Tribal Area/Forest Zone/Green Zone Agricultural Zone
 - b) Absolute height of buildings shall not exceed 9 metres and number of storeys shall not exceed ground plus one upper
 - c) Activities mentioned in Annexure-C may be permitted by the monitoring committee subject to State / local rules and regulations.
 - d) Any new construction in other areas of the eco-sensitive zone will require prior approval of the monitoring committee.

(b) Industrial Units: -

- (i) Location of industries shall be only in the designated industrial areas or estates and has to be as per guidelines drawn up by the Government of Maharashtra as well as the guidelines issued from time to time by the Ministry of Environment and Forests.
- (ii) In drawing up guidelines, the Master Plan shall specify the industries that are completely prohibited, those that can be permitted after an appraisal, the requirements and procedures of which are specified, and those that may be permitted provided certain criteria are met which should be specified.

Provided that nothing in these guidelines shall conflict with the provisions of the Environment Impact Assessment Notification of January 27, 1994 of the Central Government and as amended from time to time.

- (iii) In future, only non polluting, non hazardous small scale and service industries, floriculture, horticulture or agro based industries producing products from indigenous goods from the eco sensitive zone shall be permitted.

(c) Quarrying and Mining: - Quarrying and Mining activities shall be banned in the Eco-Sensitive Zone. No fresh mining lease shall be granted in the Eco Sensitive Zone. However, the Monitoring Committee shall be the authority to give special permission for limited quarrying of materials required for the construction of local residential housing and traditional road making and maintenance work in Matheran municipal council area only;

Provided that such quarrying is not done on steep hill slopes or areas with a high degree of erosion or on forestlands.

(d) Trees: - There shall be no felling of trees whether on Forest, Government, Revenue or private lands within the Eco-Sensitive Zone, without the prior permission of the State Government in case of forest land, and the respective District Collector in case of Government, Revenue and private land, as per procedure which shall be prescribed by the State Government, provided that the District Collector shall not delegate this power to any subordinate officer below the rank of Sub-Divisional Officer.

(e) Tourism: - Tourism activities shall be as per a Tourism Master Plan, with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development, to be prepared by the Department of Tourism of the State Government in consultation with the Ministry of Tourism of Government of India and approved by the Ministry of Environment & Forests. The Tourism Master Plan shall also form a component of the Zonal Master Plan. There shall be a ban on new and additional tourist facilities like hotels, restaurants, inns, lodging and boarding houses, etc. within Matheran Municipal council area till the Tourism Master Plan is approved by the Ministry of Environment and Forests.

The Tourism Master Plan shall be based on a detailed Carrying Capacity Study of the Eco-Sensitive Zone which may be carried out by the State Government and submitted to the Ministry of Environment & Forests for approval within 2 years of the date of this Notification. All new tourism activities, developments for tourism/expansion of existing tourism activities shall be permitted only within the parameters of this tourism plan or carrying capacity study. Till the Tourism Master Plan is submitted to Ministry of Environment & Forests for approval, new tourism activities and developments for tourism expansion of existing tourism activities shall be permitted only after a detailed analysis is carried out and approved by the Monitoring Committee subject to guidelines laid down by Ministry of Environment & Forests.

(f) Natural Heritage: - The sites of valuable natural heritage in the zone shall be identified, particularly rock formations, waterfalls, pools, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides etc. and plans for their conservation in their natural setting shall be incorporated in the Master Plan. Strict guidelines shall be drawn up by the State Government to discourage construction activities at or near these sites including under the garb of providing tourist facilities. All the gene pool reserve areas in the zone shall be preserved. The State Government may draw up proper plans for their conservation or preservation within one year from the date of publication of this Notification. These plans shall form a part of the Master Plan.

(g) **Man-made heritage:** - Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetical, and cultural significance shall be identified and plans for their conservation, particularly their exteriors (and wherever deemed appropriate their interiors also) shall be prepared and incorporated in the Master Plan within one year from the date of publication of this Notification. Guidelines may be drawn up by the State Government to regulate building and other activities in the Eco-sensitive zone, particularly in Matheran municipal limits, so that the special character and distinct ambience of the town and the eco sensitive zone are maintained.

(h) Development or construction activity at or around heritage sites (both natural and man-made) shall be regulated in accordance with the Model Regulation on Conservation of natural and man-made Heritage formulated by the Ministry of Environment & Forests in 1995 as amended from time to time and circulated to all State Governments and Union Territory Administrations) or any other statutory provisions of the State Government, whichever is stricter.

(i) **Ground Water:** - Extraction of ground water shall be permitted only for the bona fide agricultural and domestic consumption of the occupier of the plot. Extraction of ground water for industrial/commercial/residential estates/complexes shall require prior permission from the State Ground Water Board. No sale of ground water shall be permitted except with prior approval of the Monitoring Committee.

(j) **Use of plastics:** - The Monitoring Committee shall regulate the use of plastics and tetrapacks within the Eco Sensitive Zone. Plastic bags within Matheran municipal limits shall be completely banned.

(k) **Protection of Hill Slopes:** - The Master Plan shall indicate areas on hill slopes where construction shall not be permitted and there shall be no construction on steep hill slopes or with a high degree of erosion.

(l) **Discharge of effluents:** - The discharge of any untreated effluent is prohibited within the Eco Sensitive Zone. No effluent, either treated or untreated, shall be permitted to be discharged into any water body/ water source within the zone.

(m) **Solid Wastes:** - The local authorities shall draw up plans for the segregation of solid wastes into biodegradable and non-biodegradable components. The biodegradable material may be recycled preferably through composting or vermiculture; the inorganic material may be disposed of at environmentally acceptable locations. No burning or incineration of solid wastes shall be permissible within Matheran Municipal Area. It is clarified that the term solid wastes include domestic, industrial, commercial and garden wastes.

(n) **Natural Springs:** - The catchment area of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation of those that have run dry in their natural setting shall be incorporated in the Master Plans. Strict guidelines shall be drawn up by the State Government to ban development activities at or near these areas.

(o) **Traffic:** - No vehicular traffic shall be permitted within the municipal limits of Matheran, except ambulance and fire engine.

3. Monitoring Committee:

- (a) The Government of India in the Ministry of Environment & Forests shall constitute a Monitoring Committee to ensure compliance with the provisions of this notification. Besides the above provisions of the notification, the monitoring committee shall have the powers to regulate and control noise pollution within the Eco Sensitive Zone. An outstanding/eminent person with sufficient managerial/administrative experience and understanding of local problems shall chair the committee. The Monitoring Committee shall include representative(s) of the Ministry of Environment and Forests, Central Pollution Control Board and at least two representatives of non-government organisations working in the field of environment (including heritage conservation). Collector of Raigad District, Maharashtra shall be a member/convenor. The membership of the committee including Chairman shall not exceed ten.
 - (b) It shall be the duty of the Monitoring Committee to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 if offences under the said Act come to its notice.
 - (c) The Committee or any officer or member of the Monitoring Committee authorised by the Committee shall be authorised to file complaints under the Environment (Protection) Act, 1986.
4. In exercise of the powers conferred by Sub-section (3) of Section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986, read with Section 23 of the said Act, the Ministry of Environment and Forests, Government of India empowers the Monitoring Committee to discharge the functions specifically enumerated in the Notification and to do all things incidental thereto, (except the function as are required to be performed by the Central Government under the provisions of the Environment Impact Assessment Notification of 27th January, 1994 as amended from time to time).

5. **Appeal:**

- (a) An appeal from any order of the Monitoring Committee shall lie with the Ministry of Environment and Forests: provided that the appeal shall be made within sixty days of date of receipt of the order by the affected person s, institutions/organisations.
- (b) The Ministry of Environment and forests shall dispose of the appeal within thirty days of date of receipt of the appeal.

I [F.No. J-20011/1/99-I.A.-III]
Dr. V. RAJAGOPALAN, Jt. Secy.

Annexure-B

BOUNDARY OF MATHERAN ECO SENSITIVE ZONE

EAST: The road from Karjat in the southeast to the Urbanisable-1 Zone of Badlapur in the northeast via Neral and Wangani.

NORTH: From Badlapur in the northeast to the northernmost limits of Navi Mumbai Municipal Corporation in the northwest, the boundary of the Forest Zone / Green-1 Zone / Green-2 Zone / Quarry Zone with the Industrial Zone / Urbanisable-1 Zone / Urbanisable-2 Zone.

WEST: From the northernmost limits of Navi Mumbai Municipal Corporation in the north-west to Chowk in the south-west, the boundary of the Forest Zone / Green-1 Zone / Green-2 Zone / Quarry Zone with the Industrial Zone / Urbanisable-1 Zone / Urbanisable-2 Zone till the Forest Zone / Green-1 Zone / Green-2 Zone / Quarry Zone meets the Panvel-Karjat railway line in the west-south-west, then along the railway line till the outflow of Morbe Dam and then along the outflow till it meets the Chowk-Karjat road.

SOUTH: From where the outflow of Morbe Dam crosses the Chowk-Karjat road in the southwest to Karjat in the southeast.

From the above bounded Zone: -

- a) The area of Karjat municipality is excluded
- b) In Neral and Wangani the area under the Layout prepared as a part of the final Regional Plan 1973 is excluded

The entire municipal area of Matheran is included.

Note: The classification of zones referred to above is as per the sanctioned Regional Plan of the Mumbai Metropolitan Region, December 1999.

LIST OF VILLAGES OF MATHERAN ECO SENSITIVE ZONE

DISTRICT: RAIGAD

TEHSIL: KARJAT

Sr. No.	Village	
1.	Asai	
2.	Ashane	Partial
3.	Bamnoli	
4.	Bandivali	
5.	Bedisgaon	
6.	Bekare	
7.	Bhadwal	
8.	Bhansoli	Partial
9.	Bhutiwali	
10.	Borle	Partial
11.	Chinchwali	Partial
12.	Damat	Partial
13.	Dhamote	Partial
14.	Diksal	Partial
15.	Garpoli	Partial
16.	Halivali	Partial
17.	Jite	Partial
18.	Kirwali	Partial
19.	Koshane	Partial
20.	Mamdapur	Partial
21.	Mangaon Tarf Waredi	Partial
22.	Matheran	
23.	Neral	Partial
24.	Pali Tarf Waredi	
25.	Savargaon	Partial
26.	Shelu	Partial
27.	Umroli	Partial
28.	Vadavali Tarf Waredi	Partial
29.	Wanjale	Partial

te 1. Entire municipal area of Matheran is included.

TEHSIL: KHALAPUR

Sr. No.	Village	
1.	Bhilawale	Partial
2.	Borgaon Bk.	
3.	Borgaon Kh.	
4.	Chowk Maniwali	Partial
5.	Hatnoli	Partial

Sr. No.	Village	
6.	Lodhivali	Partial
7.	Morhe	
8.	Nadhal	Partial
9.	Nanwali	
10.	Padaghe	
11.	Pali Bk.	Partial
12.	Sondewadi	
13.	Wad Vihar	
14.	W. arose Tarf Wankhal	
15.	Wawarle	Partial

TEHSIL: PANVEL

Sr. No.	Village	
1.	Adai	
2.	Akuli	
3.	Ambhe Tarf Taloje	
4.	Ambhe Tarf Waje	
5.	Ambivali	
6.	Barwai	Partial
7.	Beravali	
8.	Bhingar	Partial
9.	Bhokarpada	Partial
10.	Bonshet	
11.	Borle	Partial
12.	Chal	
13.	Cheravali	
14.	Chikhale	Partial
15.	Chinchavali Tarf Taloje	
16.	Chinchavali Tarf Waje	
17.	Chindharan	
18.	Chipale	
19.	Daharang	
20.	Devad	Partial
21.	Devichapada	Partial
22.	Dhamani	
23.	Dhodani	
24.	Dundre	
25.	Gadhe	
26.	Ghot	
27.	Ghot Camp	
28.	Hangram	
29.	Hedutane	
30.	Kanpoli	
31.	Karambeli Tarf Taloje	
32.	Karavale Bk	
33.	Kevale	

Sr. No.	Village	
34.	Khairwadi	
35.	Khanav	
36.	Kherane Kh.	
37.	Kondale	
38.	Kondap	
39.	Koproli	
40.	Loniwali	
41.	Machiprabal	
42.	Mahalungi	
43.	Mahodar	
44.	Maldunge	
45.	Moho	Partial
46.	Mohope	Partial
47.	Morbe	
48.	Nagzari	
49.	Nere	
50.	Nevali	
51.	Nitalas	
52.	Nitalc	
53.	Pale Bk.	
54.	Pali Bk.	
55.	Pali Kh.	
56.	Penghar	Partial
57.	Poyanje	Partial
58.	Ritghar	
59.	Roadpali	Partial
60.	Sangade	Partial
61.	Sangatoli	
62.	Shilottar Raichur	
63.	Shirvali	
64.	Shivansai	
65.	Shivkar	Partial
66.	Taloje Majkur	Partial
67.	Tamsai	
68.	Tembhode	Partial
69.	Tondhare	Partial
70.	Turbhe	Partial
71.	Umroli	
72.	Usarli Bk.	
73.	Vakadi	
74.	Valap	
75.	Valavali	Partial
76.	Vavanje	
77.	Vihighar	
78.	Wajapur	
79.	Waje	
80.	Wangani Tarf Taloje	

Sr. No.	Village	
81.	Wangani Tarf Waje	
82.	Wardoli	

DISTRICT: THANE

TEHSIL : KALYAN

Sr. No.	Village	
1.	Bhal	Partial
2.	Dhamtan	Partial
3.	Dwarli	Partial
4.	Vadavali Bk.	
5.	Vasar	Partial

TEHSIL: THANE

Sr. No.	Village	
1.	Bale	
2.	Narivali	Partial
3.	Vaklan	Partial

TEHSIL: ULHASNAGAR

Sr. No.	Village	
1.	Ambhe	
2.	Amboshi	
3.	Asode	
4.	Bandhanwadi	
5.	Bendshil	
6.	Bhoj	
7.	Bohonoli	
8.	Burdul	
9.	Chamtoli	Partial
10.	Chikhaloli	Partial
11.	Chinchvali	
12.	Chinchvali Bk.	
13.	Chirad	Partial
14.	Dahivali Tarf Chon	
15.	Dhavale	Partial
16.	Dhoke	
17.	Done	Partial
18.	Goregaon	Partial
19.	Gorpe	
20.	Jambhivali	Partial
21.	Joveli	Partial
22.	Kakadwal	

Sr. No.	Village	
23.	Kakole	
24.	Karavale Kh	
25.	Kasgaon	Partial
26.	Katrap	Partial
27.	Khard	
28.	Kharvai	Partial
29.	Khuntavali	
30.	Kumbharli	
31.	Kushavali	
32.	Mangrul	
33.	Manjarle	Partial
34.	Mankivali	Partial
35.	Narhen	
36.	Nevali	
37.	Pale	Partial
38.	Pali	Partial
39.	Posari	
40.	Sakharoli	
41.	Sape	Partial
42.	Savaroli	
43.	Shivavali	
44.	Shinggaon	Partial
45.	Tan	
46.	Usatane	
47.	Vangan	Partial
48.	Varade	
49.	Wadi	

Annexure-C

Permissible developmental activities in Matheran Eco-Sensitive Zone

(The classification of zones is as per the sanctioned Regional Plan of the Mumbai Metropolitan Region, December 1999)

1. FOREST ZONE

- 1.1 When any land is situated outside Reserve Forest, Protected Forest, Acquired Forest or Forests as defined as per the Supreme Court's Order dated 12.12.1996, the development of such land shall be regulated in accordance with the provisions for Green Zone-2.

2. GREEN ZONE-2

2.1 The permissible uses in Green Zone-2 (G-2 Zone) are as follows:

- a) Farm buildings for the bona fide use of the holder of any land assessed or held for the purpose of agriculture, to use for the better cultivation of the land. Provided that the area of the agricultural holding is 0.4 ha or more.
- b) Horticulture, floriculture, and, agricultural and allied activities of rice and poha mill, poultry farms, cattle stables, piggeries and sheep farms.
- c) Religious places, crematorium and cemetery.
- d) Schools, pre-primary school and health centre, on plot not less than 0.4 ha
- e) Clinics and dispensaries.
- f) roads and bridges, railways, dams, pipelines, electricity transmission lines communication towers.

2.2 The minimum plot size shall be 0.4 ha.

2.3 FSI and Ground Coverage

Permissible Use in 2.1	FSI	Ground coverage
a)	Plinth size of all buildings shall not exceed 150 sq. m.	
b) c) d) e)	0.05	5%

GREEN ZONE-1

3.1 The permissible activities in Green Zone-1 are as follows:

- a) Farm buildings for the bona fide use of the holder of any land assessed or held for the purpose of agriculture, to use for the better cultivation of the land. Provided that the area of the agricultural holding is 0.4 ha. or more.
- b) Holiday resorts and holiday homes.
- c) Educational, medical, social, cultural and religious institutions along with residential quarters and shops for the staff on plots not less than 2.5 ha.

- d) Schools, pre-primary school and health centre, on plot not less than 0.4 ha.
- e) Clinics, dispensaries and health centres,
- f) Storage of LPG cylinders.
- g) Horticulture, floriculture, and, agricultural and allied activities of rice and poha mill, poultry farms, cattle stables, piggeries and sheep farms.
- h) Religious places, crematorium and cemetery.
- i) Parks, gardens, play fields, swimming pools, camping grounds.
- j) Roads and bridges, railways, dams, pipelines, electricity transmission lines and communication towers.

3.2 The minimum plot size shall be 0.4 ha.

3.3 FSI and Ground Coverage

<u>Permissible Use in 3.1</u>	<u>FSI</u>	<u>Ground coverage</u>
a)	Plinth size of all buildings shall not exceed 150 sq. m.	
b) to e)	0.1	10%
Others	0.05	5%

4. URBANISABLE ZONE-2

4.1 The permissible activities in Urbanisable Zone-2 are:

- a) Farm buildings for the bona fide use of the holder of any land assessed or held for the purpose of agriculture, to use for the better cultivation of the land. Provided that the area of the agricultural holding is 0.4 ha. or more.
- b) Houses for residential purposes
- c) Retail shops, whole sale shops, restaurants and banks
- d) Government offices
- e) Schools, pre-primary school and health centre, on plot not less than 0.4 ha.
- f) Clinics, dispensaries and health centres
- g) Non polluting scientific institutions
- h) Garages, petrol pumps, automobile repair workshops
- i) Parks, gardens, play-fields and swimming pools
- j) Cemeteries and crematoria
- k) Horticulture, floriculture, and, agricultural and allied activities of rice and poha mill, poultry farms, cattle stables, piggeries and sheep farms
- l) With the prior approval of the Monitoring Committee, hotels, tourists resorts, holiday homes, motels and club houses
- m) With prior approval of the Monitoring Committee, public services and utility establishment of water treatment plant, sewage treatment plant, solid waste treatment and disposal facilities, electricity sub-station, gas works, fire brigade, police station, telephone exchange, bus shelters, terminals and depots
- n) Roads, bridges, dams, railway lines and related facilities, pipelines, electricity transmission lines and communication towers

- 4.2 The minimum plot size shall be 2,000 sq. m.
 - 4.3 Permissible FSI shall not exceed 0.2.
 - 4.4 Permissible ground coverage shall not exceed 20%.
5. URBANISABLE ZONE-1
- 5.1 In preparing the sub-zonal Master Plan for Matheran the recommendations of the report titled Matheran: A Comprehensive Heritage Listing Proposal commissioned by the Mumbai Metropolitan Region Heritage Conservation Society shall be taken into account.
 - 5.2 The development of lands within the Urbanisable Zone-1 of Neral and Wangani for which no Development Plan, Planning proposal, Town Planning Scheme or Development Control Regulations exist shall be regulated in accordance with the provisions for Green Zone-2.
6. GAOTHAN and GAOTHAN EXPANSION
- 6.1 The following provisions irrespective of Zones shall regulate Gaothan and gaothan expansion.
 - 6.2 The boundary of the gaothan shall be as shown in the revenue maps when the Regional Plan came into force.
 - 6.3 Gaothan expansion is the area within 200 m. from the gaothan boundary. If more than three-fourths of a plot / sub-plot falls within 200 m. then the entire plot / sub-plot shall be considered as a part of the gaothan expansion. Land within gaothan expansion shall be used only for / by the bona fide residents of the gaothan
 - 6.4 The lands in gaothan may be used for any of the following purposes:
 - a) Residential
 - b) Retail shops, restaurants, banks, hair-cutting saloons, flour mills, ration shop, bicycle repair shops and automobile repair shops
 - c) Schools
 - d) Community centres and other social institutions
 - e) Religious places
 - f) Clinics, dispensaries and health centres
 - g) Essential public services and utilities including local Government offices
 - h) Stables for domestic animals subject to limit of 5 animals on each plot
 - i) Traditional household industries
 - j) Storage of crop, fodder, manure, agricultural implements and other similar needs
 - k) Parks, gardens and playgrounds
 - l) Public conveniences

- m) Storage of fuels for domestic and commercial purposes like hotels, restaurants and guesthouses.

6.5 FSI and Ground Coverage.

Area	FSI	Ground coverage
Gaothan	1.00	-
Gaothan expansion	0.40	40%